



जान संपादकीय

चीन की नामकरण रणनीति

भारत के पूर्वान्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के 11 झला का नाम बदलने के लिए चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसमें दो रिहायशी इलाके हैं, पांच पर्वतों की चौटियाँ हैं, दो नदियाँ हैं और दो अन्य इलाके हैं। अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों के लिए चीनी, तिब्बती और पिनयिन नामों का तीसरा सेट जारी हाल ही में चीन द्वारा जारी किया था। चीन, अरुणाचल प्रदेश में 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है और नाम बदलने की यह चाल सीधे तौर पर भारतीय अधिकार क्षेत्र में दखलांगजी की एक और नापाक कोशिश है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कैबिनेट की स्टेट कार्डिसिल के नियमों के तहत इन नामों को बदला गया है। चीन के विशेषज्ञ इसे कानूनी तौर पर सही ठहरा रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दक्षिण-पश्चिमी चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र में इन नामों को बदला है। चीन के अखबार में जिसे दक्षिण-पश्चिम शिजांग स्वायत्त क्षेत्र बताया गया है, वह दरअसल अरुणाचल प्रदेश

ह। गारतलब ह कि चीन ने 1962 म भारत क साथ युद्ध म अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया और चीन की सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। मैकमोहन रेखा ही भारत और तिब्बत के बीच सीमाओं का निर्धारण करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटेन के प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने शिमला पर हस्ताक्षर कर इस सीमा रेखा को तय किया था। मैकमोहन रेखा को दिखाने वाला नक्शा पहली बार वर्ष 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया था। लेकिन चीन-शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्रियों के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जाता रहा है। भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य पर अब नाम बदलने कर हक्क दिखाने की कोशिश चीन ने की है। अपने इस पड़ोसी राज्य की हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कि हमने ऐसे रिपोर्टें देखी हैं। ये पहली बार नहीं हैं जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। नए नाम रखने के प्रयासों से ये सच्चाई नहीं बदलेगी।

किसी भी स्वायत्त, सम्प्रभु राज्य की सीमा में अगर कोई अतिक्रमण करे या उसके स्थलों के नाम बदले तो यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो भारत ने प्रकट की। सवाल ये है कि यही प्रतिक्रिया भारत कितने बार और कब तक देने का इरादा रखता है। दरअसल चीन ने पहली बार साल 2017 में छह जगहों के और फिर 2021 में 21 जगहों के नामों को अपने हिसाब से बदला था। तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ऐसे जवाब के बाद भी चीन अगर छह साल में तीन बार नाम बदलने की कोशिश करे, तो इसका अर्थ यही है कि या तो वह भारत के जवाब को सुन नहीं रहता है, या सुनने के बावजूद उसे मान नहीं रहा है। नाम बदलने के अलावा भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी चीन करता रहता रहा है, गलवान के जखम इसके गवाह हैं। चीन की इस अतिक्रमणकारी नीति और विस्तारवादी एजेंडे से भारत को सख्ती से निपटना होगा लेकिन इसकी शुरूआत तभी होगी, जब सरकार इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। अभी तो सरकार इसे नकारने की मुद्रा में ही दिखती है। प्रधानमंत्री ने अब तक चीन का नाम लेकर आलोचना नहीं की। इंडोनेशिया में शिष्टाचार के नाते अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद उठकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने पहुंच गए, तब भी उन्हें ये सख्त संदेश देना चाहिए था कि शिष्टाचार और नैतिकता का अर्थ हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। गलवान के बाद कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के नजदीक चीन पूरी बसाहट का इंतजाम कर रहा है। इन खबरों में क्या सही है, क्या गलत, इसका खुलासा तो तभी होगा जब सरकार कोई स्पष्ट बयान जारी करेगी। लेकिन सरकार सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के मसले पर बात ही नहीं करती। और विपक्ष सवाल उठाए, तो जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मीडिया में पाकिस्तान को देश के बड़े दुश्मन की तरह पेश किया जाता है, उसकी खस्ता आर्थिक हालात पर तंज कर से जाते हैं। जबकि आज के हालात में चीन से सबसे अधिक चुनौती भारत को मिल रही है। जब गलवान में भारतीय-चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, तो भारत ने सख्ती दिखाने के नाम पर चीन के कुछ ऐप्स प्रतिवर्धित कर दिए थे और व्यापार पर रोक लगाने की बात की थी। हालांकि व्यापार का सिलसिला कई तरह से चलता रहा, केवल आम जनता के लिए चीनी सामान का बढ़िश्कार राष्ट्रवाद के नए मंत्र के रूप में पेश किया गया था। अभी कुछ बक्स पहले विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने सामान्य बुद्धि का हवाला देते हुए कहा था कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस जवाब से जाहिर हो रहा है कि भारत सरकार चीन को उसकी सीमाओं में रहने की नसीहत देने की जगह अपनी सीमाओं को समझने में लगी है। इसलिए चीन की हिम्मत बढ़ती जा रही है। इससे पहले की पानी सिर के ऊपर से

ਸਾਬ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੀ ਫੁਨਿਆ

सुशील कट्टी

भारत की जी-20 की अध्यक्षता मोदी के लिए इस बात को और महत्वपूर्ण बना देता है कि वह राजनीतिक विरोधियों के बारे में वैसे बातें बोलना बढ़ करें मानो वे दीमक और द्रुमन हों जिनसे मौत तक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। भारत का चुनावी लोकतंत्र भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक साथ संभालने के लिए काफी बड़ा और जीवंत है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के आकार के कुछ और राजनीतिक दलों के लिए जगह है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्यूकी मारने के बाद, जर्मनी की बारी थी। राहुल गांधी की अयोग्य संसद की हैस्यत वाली स्थिति दोनों लोकतंत्रों को फेरेशन कर रही है। गहुल गांधी की लंदन टिप्पणी जो नहीं कर सकी, वह लोकसभा से उड़ेंगी।

उठकर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी को यह भी साबित करने की जरूरत न रही कि न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ भारत में लोकतंत्र की भौत से बेखबर थे। सिक्का पिरा और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दोनों ने इसके ठनकने की आवाज को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। कांग्रेस संसद दिविजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए टीटोविका और जिसने भाजपा की जोरदर नाराजगी अंजित की, वह भाजपा जो नहीं जानती कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को निशाना बनाने पर कांग्रेस का वापा होता है। यह इंदिरा गांधी और यहां तक कि राजीव गांधी के साथ भी हुआ। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लक्षित हमलों

आंकड़ों का सच-झूठः जनता कैसे करें भरोसा

अरविन्द मोहन

70 फासदा स ज्यादा घरा क चूल्ह क
लिए लकड़ी, उपले या खेती से निकले
ठंडल या भूसे पर ही निर्भर हैं। झारखंड
के 25 फीसदी से भी कम घरों का चूल्हा
एलपीजी से जलता है जो देश में सबसे
कम है। इसी सर्वेक्षण में यह भी उत्तागर
हुआ कि 15 से 24 साल के 16 फीसदी
पुरुष और 44 फीसदी महिलाएं न तो
स्कूल-कॉलेज जाते हैं न काम करते न
ही कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं। आंकड़े
सरकारी हैं इसलिए बात भरोसे से की जा
सकती है। लेकिन इन आंकड़ों की चर्चा
मीडिया में इतनी कम क्यों हुई? यह हैरान
करता है। बात ग्रामीण और शहरी भारत
में शुद्ध पेय जल पहुंचाने और घर-घर
शौचालय बाले स्वच्छता मिशन की
उपलब्धियों और नाकामियों की है। और
आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के
हैं। सर्वेक्षण के 78वें दौर के मल्टीपल
इंडीकेटर सर्वे के अनुसार आज भी
ग्रामीण भारत के चार में से तीन घरों तक
स्वच्छ पेयजल की पाइप बाली व्यवस्था
नहीं है।

शहरी इलाकों की स्थिति अच्छी है लेकिन यहां भी एक तिहाई घर अभी इस सुविधा से वंचित हैं। करीब 21 फीसदी घरों तक अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है। बहुत बड़े आधार वाले इस सर्वेक्षण से यह भी जाहिर हुआ कि अभी भी देहाती आवादी का आधा हिस्सा अभी भी जलावन की लकड़ी से ही खाना बना रहा है। और अगर कोई चाहे तो यह भी कह सकता है कि उज्ज्वला योजना ने देश की आधी से अधिक महिलाओं को चूल्हा फूंकने से मुक्ति दिला दी है और शौचालयों की दखल असरी फीसदी से कुछ कम घरों तक हो चुकी है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति झारखण्ड और ओडिशा की है। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन के नौ वर्षों के साथ यदि हम यूपीए शासन के दस साल और उसके लोकप्रिय और कार्यकुशल मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तपरता और मेहनत को देखें तो लोगेगा कि अभी जो स्थिति होनी

चाहिए थी वह कोसों दूर है। जाहिर है इस काम में जो संसाधन लगाना चाहिए और जो रणनीति अपनाई जानी चाहिए वह अभी भी दूर है। और शायद हम इन बातों के महत्व को अपने लोगों के मन में बैठाने में भी असफल रहे हैं। स्वच्छता मिशन का प्रचार बहुत हुआ है लेकिन उतना असर नहीं दिखाता। इसकी तुलना में बैंक में खाता खोलने, मोबाइल पहुंचाने, बिजली पहुंचाने या सड़क मार्ग से देश के हर गांव को जोड़ने के मामले में शायद बेहतर उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और पेयजल मिशन या स्वच्छता का काम अकेले इन्हीं दो सरकारों का भी नहीं है। इनका हिसाब तो बीस साल का भी नहीं है। आजाद देश का हिसाब तो पचहत्तर साल का है और अंगरेजी हुक्मनूमत ने भी ये व्यवस्थाएं की थीं- खासकर शहरी क्षेत्रों के लिए। हम लाख दावे करें पर अभी भी अधिकांश शहरों के पेयजल और मल-निकासी की पुरानी व्यवस्थाएं ही आगे के लिए भी आधार बनी हैं। कई जगह तो मुगल दौर की या उस काल की व्यवस्थाएं आज भी काम कर रही हैं। मजे की बात यह है कि हमारे राष्ट्रपिता की प्राथमिकता में यह चीज चंपारण अधिक महिलाओं को घूला फूंकने से मुक्ति दिला दी जा सकता है कि उज्ज्वला योजना ने देश की आधी से ही दिखने लगी थी। तब भी चंपारण के कुएं, तालाबों की सफाई और उनमें पोटेशियम परमैग्नेट के घोल से सफाई का कार्यक्रम जोर-शोर से चला था। तब के चंपारण में धेंधा, मलेरिया और चर्मरोग इतना ज्यादा था कि गांधी ने इस काम को तीनकठिया से मुक्ति के बाद प्राथमिकता के आधार पर किया। खास इसी के लिए डॉ. देव को बुलाया गया और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से स्वयंसेवक बुलाए गए थे। इतना ही नहीं, हमारे एक और बड़े जननेता डॉ. राममनोहर लोहिया तो घर में शौचालय होना और औरतों को चूल्हा फूंकने से मुक्ति दिलाए बगैर औरत की आजादी की बात करना भी गुनाह मानते थे। बहुत बाद तक समाजवादी आंदोलन के लोग बाकी समाज में काम अपने कार्यकार्ताओं के घर में शौचालय ढूँढते थे और न होने से ही खाना बना रहा है। और अगर कोई चाहे तो यह भी कह सकता है कि उज्ज्वला योजना ने देश की आधी से ही और शौचालयों की दखल अस्सी फीसदी से कुछ कम घरों तक हो चुकी है परं डॉ लगाते थे रघुवंश बाबू के समय लोहिया की इस सुक्ति की चच बार-बार होती थी। और गांधी ते स्वच्छता मिशन का प्रतीक चिह्न ही बगए हैं। आजकल भले इस प्रचार में कुछ कमी दिखती है वरना गांधी का चेहरा चश्मा और खड़ाऊ ही मिशन का प्रतीक थे।

उस हिसाब से देखें तो अभी इस मामले में काफी काम बाकी है बल्कि अनेक राज्यों में पाइप और नल लाले पानी के हिसाब तो इस सर्वेक्षण में नगण्य बताया गया है। सर्वे में घर या आंगन या फिर सार्वजनिक नल तक पाइप के सहारे पानी

पहुँचने, नल-कूप से पानी, चापाकल/हैंडपंप, ढके या छत वाले कुएं, टैंकर, बोतल या जार में बंद पानी की आपूर्ति को भी गिना गया और इस हिसाब से 95 फीसदी से ज्यादा लोग पेयजल प्राप्त कर रहे थे। बिहार में हाल के दिनों में पाइप वाले पेयजल का काफी काम हुआ है लेकिन वह इस दौर वाले सर्वे में नहीं आ पाया। पर असम, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा पेय जल की उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। कई जगह तो साफ पानी की उपलब्धता कराने में नब्बे फीसदी घरों तक नहीं हो पाई है। इसी तरह घर के अंदर शौचालय बनवाने के मामले में बिहार, झारखण्ड और ओडिशा सबसे नीचे हैं। यहां बिना शौचालय वाले ग्रामीण घरों का अनुपात तीस फीसदी से ज्यादा है। अब कई राज्यों में यह अनुपात साठ फीसदी से ऊपर भी गया है। अभी भी छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मध्यप्रदेश के 70 फीसदी से ज्यादा घरों के चूल्हे के लिए लकड़ी, उपले या खेती से निकले डंठल या भूसे पर ही निर्भर हैं। झारखण्ड के 25 फीसदी से भी कम घरों का चूल्हा एलपीजी से जलता है जो देश में सबसे कम है। इसी सर्वेक्षण में यह भी उजागर हआ कि 15

से 24 साल के 16 फीसदी पुरुष और 44 फीसदी महिलाएं न तो स्कूल-कॉलेज जाते हैं न काम करते न ही कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं। पुरुषों के मामले में उत्तराखण्ड, ओडिशा, केरल और दिल्ली का दर्जा काफी नीचे था जबकि औरतों के मामले में उत्तरप्रदेश, असम, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर नीचे था। मोबाइल फोन के मामले में लगभग आधी आबादी की पहुंच हो चुकी है और बैंकों में खाते के मामले में सफलता की दर लगभग नब्बे फीसदी तक पहुंच गई थी। अब यह सर्वे के दायरे के बाहर का सवाल है कि उनमें कितना पैसा था और कितने खाते सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए तो लिए गए थे।

रकम के डायरेक्ट ट्रासफर का लिए खुल थे।

सुपारी का लेन-देन और कब्र की खुदाई ही है

डा. दंपक पाचपार

आधार भारत मादा जस व्याकृत का, जा चमत्कारक प्रति से देश का विकास करने का दावा करते हुए तो यह तारी समस्याओं को किसी जातु की छड़ी से बचाव करने के तरीके बतलाया करते थे; और उसका अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक ले जाने की वांचते करते थे, आज अपनी एक भी उपलब्धि के लिये नहीं गिना पा रहे हैं? आखिर क्यों आज भी वे पिछली सरकारों को क्षेत्री प्रित हैं? देश को नोने पूरी तरह से बदलने का दावा कर केन्द्र की वित्ती में आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकार्यकाल 9 वर्षों के दौरान इसी मुकाम तक हुंच पाया है कि आज भी वे जनसंरोक्त के लिये ग्रेस मुद्दों एवं अपने कामों की स्पिटें पेश करने की बजाय भावनात्मक मसलें पर ही बातें करते हुए, अपने आप को निरीह, गरीब व प्रतिडिन बदलतालो रहे हैं। विकिटम कार्ड खेलने की प्रक्रिया वेस्ट वे पूरे देश को भी बेबस व बेचारा साक्षित करने पर आमादा हैं। बेशक, हर कोई जानता है कि यह उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है तिकिन वे इसकी आड़ में महत्वहीन विमर्श को ऐसा मजबूती से पेश कर रहे हैं कि सत्ता पाने की अपांटी बनी रहे। दुखद तो यह है कि वे जब भावनात्मक मुद्दों पर आधारित आसमानी आदर्श ढारे हैं तो उसे अतिरिक्त बल देने के लिये आमाजिक विभाजन का ही सहारा लेते हैं जो उसका एवं लोकतंत्र के लिये बहुत नुकसानदेह नाबित हो रहा है। रामनवमी में जिस प्रकार से याम्प्रदायिक वैमनस्यता का अतिरिक्त ज्वार दरखा गया है, वह यहीं बता रहा है कि अनेक लोगों ने भाजपा का एजेंडा यही रहेगा। यानीकहित पीछे, बहुत पीछे छूटे जा रहे हैं। युक्तिसान जनसामान्य को होगा, लाभान्वित होगा जननीतियों व पूँजीपतियों का गठजोड़। सबाल यह है कि व्या मोदी प्रणीत सरकार के 9 साल के कथित महान कामों का हासिल इतना ही है कि भारत का लोकतंत्र 2024 के आम

दरअसल ये लोग ही भाजपा की असली परिसम्पत्ति हैं। ये वे हैं जिनके लिये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाएं कोई मायने नहीं रखतीं। ये ही वे लोग हैं जो नागरिक चेतना, अधिकारों विवेक से शून्य हैं। वे हर कीमत पर साम्प्रदायिक अलगाव व सामाजिक भेदभाव को बनाये रखने के पक्षधर हैं- सरकार के अपकर्मों की अनदेखी करते हुए और अपने बच्चों का भविष्य स्वाहा करके भी। अपनी असफलताओं के अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी द्वारा अडानी से उनके सम्बन्धों को लेकर हुए हमले के कारण पहले से बौखलाये बैठे मोदी के समक्ष अगले माह के मध्य में होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा में हार का साफ व बड़ा खतरा मंडरा रहा है

चनावों की ढहलीज पर खड़ा होकर भी सपारी

के लेन-देन और कब्र खोदने से आगे नहीं बढ़ाया?

अगर विचार करें कि आखिर मोदी जैसे व्यक्ति को, जो चमककिंच गति से देश का विकास करने का दावा करते हुए सारी समस्याओं को किसी जादू की छड़ी से गयाव करने के तरीके बतलाया करते थे; और देश को अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक ले जाने की बात करते थे, आज अपनी एक भी उपलब्धि क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? आखिर क्यों आज भी वे पिछली सरकारों को कोसते फिरते हैं? उह्नें अवाम ने दो-दो बार बड़े मौके दिये हैं। फिर भी उह्नें ठोस मुद्दों पर बात करने की बजाय परिवारवाद का ढोल क्यों पीटना पड़ रहा है? क्यों वे देश की मूलभूत समस्याओं का निगरान करने की जगह पर खुद को चमकाने में सारा वक्त जाया कर रहे हैं?

गहराई में जाएं तो यही बात निकलकर सामने आती है कि जिस छवि के बल पर उह्नोंने सत्ता पाई है, दरअसल उसका कच्चूपर निकल गया है। एक-एक कर बात कर ली जाए। जिस समय मोदी की प्रधानमंत्री के लिये दावेदारी पेश की

के समाधान विकास के गुजरात मॉडल में उपलब्ध हैं जिसके निमायां यही व्यक्ति है। समय के साथ पाया गया कि वह कथित मॉडल पूँजी की तरफ ऐसा बेंगा झुका हुआ है कि जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो उस मॉडल के तहत हुए विकास से प्रभावित एक बड़े हिस्से को अस्थायी दीवार खड़ी कर ढाकना पड़ता है। उससे मॉडल के अनुरूप बनने वाली देशव्यापी सारी योजनाएं एक-एक कर नाकाम होती जाती हैं। पहली से बढ़कर दूसरी और उससे बढ़कर तीसरी सुपर फ्लॉप! उसी मॉडल के नाम पर देश की गरीब जनता अपनी मेहनत का एक-एक स्पष्टा सरकार पर भरोसा कर जन धन योजनाएं के तहत खुले सरकारी खातों में डालती है और एक सुबह यह मनहूस खबर आती है कि उनके बारे में पैसे कर्ज के रूप में लेकर उसी धरती के (गुजरात) प्रॉडिये विदेश जाकर बस जाते हैं। इसी मॉडल के तहत नोटबंदी कर जनता का सारा पैसा लटकर अपने संगठन के कार्यालय बनाये जाते हैं और चुनाव लड़े जाते हैं, रैलियां ब रोड शो होते हैं। इस मॉडल ने बताया कि

हमारे पास इतने पेस हैं कि कड़-कड़ लाख-करोड़ों का कर्ज हम उद्योगपतियों व कारोबारियों को न लौटाने के लिये तो दे सकते हैं परन्तु हमारे पास न तो कोरोना से मरते लोगों के ऑक्सीजन देने के लायक पैसे हैं और न ही उनके गरिमामय अंतिम संस्कार करने के लिये धन है। यही मॉडल सरकार को इस बात के लिये भी प्रेरित करता है कि संसद में बहस किये बगैर ऐसा कानून लाया जाये जिसके द्वारा देश भर के सारे किसानों द्वारा उत्पन्न अनाज अपने चुनिंदा व चहेते सेठों के गोदामों में डालने का विधिसम्मत प्रबंध कर दिया जाये; और जब वे विरोध करें तो उन्हें 13 माह तक दिल्ली की सीमाओं पर ठंड-बारिश-गर्मी में मरने के लिये छोड़ दिया जाये। इतना ही नहीं, सत्ता के नशे में बौखाया हुआ कोई मंत्री-पुत्र इन किसानों को कचलने का दुस्साहस भी करता है। इस मॉडल में पिछले 9 वर्षों से जारी मोदी के निजाम का योगदान ऐसा है कि उसमें जनता से मुक्त व स्वत्थ संवाद के सारे रास्ते बन्द हैं, सबाल पूछने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। मोदी न तो संसद में प्रस्तुत सवालों पर बोलते हैं और न ही प्रेस काफ्रेंस करते हैं। सूचना के अधिकार को इनना कमज़ोर कर दिया गया है कि जनता को जो जानना चाहिए, वह पूरी तरह से उसकी पहुंच से दूर कर दिया जाता है। यही मॉडल लोक गायकों से लेकर कोमेडियों तथा पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दावर करता है तथा मानवाधिकार कायफकारों को बरसों बरस जेलों में सड़ा देता है। इसके बावजूद जब इस मॉडल की पोल का कोई गम्भीर खुलासा विदेश की धरती से होता है तो सरकार बता देती है कि मोदी के मित्रों का नाम लेना मना है। इसके बारे में न तो देश का सबसे महान व्यक्ति कुछ कहता है और न ही सरकार कोई सवालों के सैधे बयान देती है। अगर कोई पूछते का साहस करता भी ही होते तो उसे मानहनि के नाम पर जेल में डालने की सजिंदें रखा जाता है। तो यहां कारण है कि मादा अपना सरकार की उपलब्धियों पर बात करने की बजाय परिवारवाद, पिछली सरकारों की गतिविधि, देश विभाजन, तुष्टिकरण की बातें करते हैं, विपक्षियों द्वारा उहें गालिया देने, उनकी कब्र खोदने या फिर उन्हें सुपारी देने का रोना रोते हैं। प्रश्न तो यह भी है कि जब अधिसंख्य जनता को यह साफ दिख रहा है कि मोदी व उनकी सरकार इतना लम्बे समय में डिलीवर करने में नाकाम रही है व उपलब्धियों के नाम पर शून्य है तो आखिर कौन हैं जो अब भी उनके समर्थक बने हुए हैं? दरअसल ये लोग ही भाजपा की असली परिस्मिति हैं। ये वे हैं जिनके लिये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाएं कोई मायने नहीं रखतीं। ये ही वे लोग हैं जो नागरिक चेतना, अधिकारों व विवेक से शून्य हैं। वे हर कीमत पर साम्प्रदायिक अलावा व सामाजिक भेदभाव को बनाये रखने के पक्षधर हैं- सरकार के अपकर्मों की अनदेखी करते हुए और अपने बच्चों का भविष्य स्वाहा करके भी। अपनी असफलताओं के अलावा हिंडनवर्ग की रिपोर्ट और गाहुल गांधी द्वारा अडानी से उनके सम्बन्धों को लेकर हुए हमले के कारण पहले से बौखलाये बैठे मोदी के समक्ष अगले माह के मध्य में होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा में हार का साफ व बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि इस राज्य को हासने के बाद मोदी व भाजपा के लिये सतत तीसरी बार लोकसभा (2024 का) का चुनाव जीतना कठिन हो जायेगा। इसलिये मोदी मूलभूत मुद्दों के बारे में एक भी शब्द कहे बगैर उनके लिये सुपारी लेने-देने, उनकी कब्र खोदने जैसी बुतुकी व आधारहीन बातें कर रहे हैं। यह न देश के हित में और न ही लोकतंत्र के हित में है क्योंकि इस विमर्श को बढ़ाने के लिये भाजपा को सामाजिक टकराव को बनाये रखना भी आवश्यक है।

हारने वाले को झानझाना मुबारक

डॉ. सरेश कमाल

डा. सुरेश कुमार वे एक सफल नता थे। गिरगिट रंग बदलने के लिए, सियार चालाकी के लिए, चोर-उच्चके लूट-पाट करने के लिए इन्हीं के पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। ज़बान से पलटना, कहीं बात से पीछे हटना, पार्टी सिद्धांत से खुद को बड़ा समझना उनके रग-रग में बसा था। वे कपड़े बदलें न बदलें पार्टी जरूर बदलते थे। ऐसा करने से उनकी नेतागिरी की धाक बनी रहती थी। सबकी अपनी-अपनी जरूरतें होती हैं। सबके अपने-अपने पेट और मुँह होते हैं। फिर नेता जी की जरूरतों का मुँह कुछ ज्यादा ही बड़ा था। न ये कभी भरा था, न भरा है और न कभी भरेगा। औलंपिक्स में लांग जंप करने वाला खिलाड़ी हार जाए तो उसकी जान लौटै है। उसी तरीके

